



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 5 फरवरी, 2005/16 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 3 फरवरी, 2005

संख्या पी०सी० एच०-एच०ए० (1) 1/92-II-1828-2030.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसकी समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 25 नवम्बर, 1997 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और जिसे इनके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), में प्रकाशित किया जाता है ;

कोई हितवद्ध व्यक्ति, जो प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आक्षेप करना/सुझाव देना चाहता है तो वह उसे, उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की

अवधि के भीतर, विशेष सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार, एस0 डी0 ए0 कम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए आक्षेप(आक्षेपों) या सुझाव(सुझावों), यदि कोई हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2005 है।

2. नियम 21 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 21 के उप-नियम(2) में, “खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् सिफारिश की जाए और उस पर उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) द्वारा इस हेतु आदेश पारित किए हों।” शब्दों, चिन्ह और कोष्ठकों के स्थान पर “कुटुम्ब के सम्बद्ध मुखिया द्वारा किए गए आवेदन पर ग्राम सभा द्वारा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित संकल्प में इसका निर्णय लिया जाए। तथापि, कुटुम्ब के विभाजन के बारे में मामले का विनिश्चय करते समय, ग्राम सभा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (13-क) के अधीन यथा परिभाषित कुटुम्ब की परिभाषा को ध्यान में रखेगी।” शब्द, अंक, चिन्ह और कोष्ठक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (1)1/-92-II, dated 3-2-2005 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 3rd February, 2005

No: PCH-HA(1)1/92-II-1828 2030.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 25th November, 1997 vide this Department notification of even number dated the 25th November, 1997 and the same are hereby published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the information of the persons likely to be affected thereby;

Any interested person who has any objection(s)/suggestions(s) with regards to the proposed amendments; may send the same to the Special Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2005.

2. *Amendment of rule 21.*—In rule 21 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, in sub-rule(2), for the words, sign and bracket “or the recommendation of the Block Development Officer, given by him after due enquiry, and order thereon by Sub-Divisional Officer (Civil) concerned.”, the words, figures, sign and bracket “on the decision of the Gram Sabha by passing a resolution by majority in its general or special meeting on an application made by the head of family concerned. However, the Gram Sabha shall take into consideration the definition of the family as defined under clause (13-A) of section 2 of the Act while deciding the matter regarding division of family.” shall be substituted.

By order,

Sd/
Secretary.

